

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 54/2010

SC No.22 to MC No. 8/2002

No. E(MPP)97/6/7

New Delhi, dated 15.04.2010

The General Managers
All Indian Railways and PUs
(As per standard mailing list)

Sub:- Training slots for Apprentices under the Apprentices Act, 1961
- Conducting fresh joint surveys

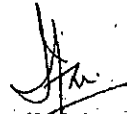
Ref:- Railway Board's letter No. E(MPP)97/6/7 dated 15.2.2000.

Zonal Railways are aware that vide above cited reference, Ministry of Railways had decided that no fresh joint survey should be undertaken in the Railways till such instructions are issued from Board. These instructions were issued then in the light of seats identified on the basis of joint survey conducted along with RDAT officials and Railways representative with a view to utilizing the seats identified and in the wake of severe criticism from the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour on the implementation of Apprentices Act on the Railways. With the advent of technological advancement and also changes in the working practices in the Railways and the fact that some skilled artisan categories have either become redundant or are not required and in lieu of new trade categories have emerged/ are emerging for which survey is required to be conducted, to identify fresh training slots, for training of Apprentices, under the Act.

Recently, the Directorate General of Employment and Training have also brought to our notice that as per the Apprentices Act 1961, it is mandatory that survey/re-survey is conducted every 2 years by the Central Apprenticeship Advisers along with the In-charge of the Establishment.

In the light of the above, it has been decided to ensure compliance of the provision of the Apprentices Act 1961 and to conduct survey/re-survey every 2 years without any ban on fresh joint survey. The number of apprentices to be engaged for training under the Apprentices Act may be suitably advised to the Railway Board after survey/re-survey have been conducted.

Para 3.5 of the Master Circular No. 81/2002 and 27/2/2002 stands modified accordingly. Kindly acknowledge receipt of the above instructions.


(K. Harikrishnan)
Director(MPP)
Railway Board.

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, with 35 spares.
3. The Secretary General FROA, Room No.256-A Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares
5. The Secretary RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.462, Rail Bhavan.
6. All Members, Departmental Council and Secretary Staff side National Council 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares
7. The General Secretary, AIRPF Association, Room No,256 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.


For Secretary/Railway Board

No. E(MPP)97/6/7

New Delhi, dated 15-04-2010

Copy to:

Shri A.S Kesai, Deputy Director General (AT), DGET Ministry of Labour & Employment, Shram Shakti Bhavan New Delhi w.r.t his letter No.DGE&T-29(4)/2009-AP dated 11.2.2010.

Copy to:

CRB, FC, ML, MM, MS, MT, DG(RHS), DG(RPF), AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml), AM(Elect), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg), AM(Project), AM(PU), AM(Sig), AM(Staff), AM(Rly Stores), AM(T&C), AM(Telecom), AM(Traffic), AM(Works), Adv.L(RS), Adv(Vig), Adv.Fin(Exp), Adv(IR), LA, OSD(MIS).
ED(Plg), ED(Accts), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDE, ED(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF, EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(T&MPP), EDME(Chg), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(PP), ED(Project), ED(Project/DMRC, EDRE, ED(safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G), JS(P), IG/RPF(Hqs), IG/RS, ED(Sig), ED(Stat & Econ), EDRS(C), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTT(M), EDTT(MC), EDTT(P), ED(T&C), EDCE(P), ED(PM), ED(PG), EDTC®, EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T), ED(W), E(Trg), E(NG)I, E(NG)II, E(G), F(E)III

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 54/2010
एस सी सं. 8/2002 का एस सी सं. 22

सं. ई (एमपीपी) 97/6/7

नई दिल्ली, दिनांक: 15.04.2010

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
(मानक डाक सूची के अनुसार)

**विषय: प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण स्लॉट -
नए संयुक्त सर्वेक्षण आयोजित करना।**

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का 15.02.2000 का पत्र सं. ई (एमपीपी) 97/6/7.

क्षेत्रीय रेलें जानती हैं कि उपर्युक्त संदर्भ के अंतर्गत, रेल मंत्रालय ने विनिश्चय किया था कि बोर्ड द्वारा ऐसे अनुदेश जारी होने तक रेलों में कोई नए संयुक्त सर्वेक्षण शुरू न किए जाएं। पहचान की गई सीटों के इस्तेमाल को देखते हुए आरडीएटी अधिकारियों और रेलों के प्रतिनिधि के साथ आयोजित संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर और रेलों पर प्रशिक्षु अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय द्वारा की गई कड़ी आलोचनाओं के मद्देनजर इन अनुदेशों को जारी किया गया था। प्रौद्योगिकीय एडवांसमेंट होने और रेलों की कार्य संचालन पद्धति में भी बदलाव होने के कारण तथा इस तथ्य को देखते हुए कि कुछ कुशल कारीगर कोटियां या तो अधिक हो गई हैं अथवा उनकी आवश्यकता नहीं है तथा उनके स्थान पर, कुछ नई ट्रेड कोटियां उभरी हैं/उभर रही हैं, जिनके लिए सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित है ताकि अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु नए प्रशिक्षण स्लॉटों की पहचान की जा सके।

हाल ही में, महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा भी इस ओर ध्यान दिलाया गया है कि प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार, स्थापना के प्रभारी के साथ केन्द्रीय प्रशिक्षु सलाहकारों द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और नए संयुक्त सर्वेक्षण पर प्रतिबंध लगाए बिना प्रत्येक 2 वर्ष में सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण आयोजित करने का विनिश्चय किया गया है। प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण के

लिए तैनात किए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण आयोजित किए जाने के बाद रेलवे बोर्ड को उपयुक्त रूप से सूचित की जाए।

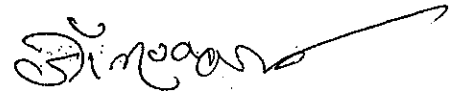
मास्टर परिपत्र सं. 81/2002 एवं 27.02.2002 के पैरा 3.5 को तदनुसार आशोधित किया जाए। कृपया उपर्युक्त अनुदेशों की पावती दें।

के. हरिकृष्णन

(के. हरिकृष्णन)
निदेशक (एमपीपी)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ।
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ।
3. महासचिव, प्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ।
4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ।
5. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 462, रेल भवन।
6. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पंक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)।
7. महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।



कृते सचिव/रेलवे बोर्ड